	Business	Time Allotted
2.	Consideration and passing of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018, after it is passed by Lok Sabha.	Two hours

2. The Committee also recommended that the House may sit beyond 6.00 p.m., as and when necessary, for the transaction of Government Legislative and other Business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Special Mentions. Shri D. Raja.

SPECIAL MENTIONS

Urging the Government to direct the CIFRI, Barrackpore to be more pro-active and help save inland fishery resources

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, the Central Inland Fisheries Research Institute at Barrackpore is the nodal agency for all inland fishery resources across the country. However, the CIFRI does not seem to have done any surveys or brought out plans for saving the millions of fishermen who face fast depleting fishery resources in all inland water bodies.

The CIFRI has regional offices all over the country. A number of petitions have been sent to the CIFRI by various concerned people to start surveys and come up with plans to protect fishery resources and the biodiversity in our rivers.

The depletion of river water, tanks and other inland water bodies has caused severe economic problems and depression in fishermen's lives. The CIFRI should take the initiative and set up surveys everywhere, starting with major rivers.

It is learnt that over the last ten years, the CIFRI has not done any major survey or made any major recommendations to the Government on how to protect fishermen who face depleting fishery resources and the impact of dams on fishery resources and fishermen.

If a dam is constructed, it should not harm fishermen's livelihood. There are designs to ensure that there is constant environmental flow of rivers and streams. Recently, the National Green Tribunal has also issued a notice to the CIFRI on the depletion of fishery resources in various South Indian rivers like the Godavari.

I request the Government to direct the CIFRI, Barrackpore to be more pro-active and help save inland fishery resources.

Demand to promote Ayurveda in Madhya Pradesh under AYUSH Mission

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं मध्य प्रदेश में आयुर्वेद का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद विज्ञान खोलने, भारतीय योग एवं नेचरोपेथी संस्थान प्रारंभ करने, आयुष मिशन के अंतर्गत शासकीय आयुष महाविद्यालयों का उन्नयन करने, आयुष औषधालयों के नवीन भवन निर्माण करने, आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय करने की केन्द्र सरकार से मांग करता हूं।

केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में आयुष उपचार के क्षेत्र में विस्तान की विशेष कार्य योजना बनाकर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे। धन्यवाद।

Demand to restore the old pension scheme

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। देश के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन बंद होने के कारण आज आंदोलनरत हैं, आज वे तमाम आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। महोदय, मैं सदन में आपके द्वारा केन्द्र सरकार से कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाली हेतु आग्रह करना चाहूंगा। 2004 के बाद आए नए कानून के मुताबिक केन्द्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बंद कर दी गयी है तथा नयी पेंशन स्कीम के मुताबिक उनकी आय का दस प्रतिशत हिस्सा प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा शेयर मार्किट में invest करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारियों को ऐसे investment से न तो कोई लाभ होगा तथा शेयर मार्किट के उतार-चढ़ाव उनकी जमा पूंजी के लिए जोखिम भरे साबित होंगे। इस पेंशन स्कीम के अनुसार एक कर्मचारी इस्तीफा देने के बाद भी सेवानिवृत्ति तक इस संचित फंड की 20 प्रतिशत से अधिक धनराशि को नहीं निकाल सकता तथा तीन साल की सर्विस के बाद ही वह बहुत ही गंभीर स्थितियों में अपने योगदान का 25 प्रतिशत हिस्सा वापस ले सकता है। क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है? National Pension Scheme के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला 60 प्रतिशत कार्पस कर योग्य होगा एवं उसके अलावा 40 प्रतिशत कार्पस अनिवार्य रूप से एक वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे में किस व्यवस्था के हित के लिए यह काम किया जा रहा है - सरकारी कर्मचारी के हित के लिए या प्राइवेट कम्पनियों के हित के लिए?

महोदय, काफी समय से कई सरकारी कर्मचारी संगठन National Pension Scheme के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, परन्तु अब तक सरकार की तरफ से उनके कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। अतः मैं सरकार से कर्मचारियों को एनपीएस से आ रही परेशानियों का संज्ञान लेने एवं उनका समाधान निकालने का अनुरोध करूंगा, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Shrimati Shanta Chhetri; not present. Shri Vijay Pal Singh Tomar.